

संपादकीय

लॉकडाउन से डरकर नहीं चलेगा काम

फैक्फैट स्कल आफ फाइनैन्स के अनुसार यदि लॉकडाउन नहीं लगते हैं तो मृत्यु दर बढ़ती है और उससे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है। इसके विपरीत अगर लॉकडाउन लगते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तकाल गिरावट आती है। वित्तीय संस्था जेफीज ने बताया है कि अमेरिका के तीन राज्य परिजनाएं, टैक्सेस और यूट्रोल में लॉकडाउन व के बहातर लगाए गए। परिणाम यह हुआ कि इन राज्यों में कोविड का फैलाव अधिक हुआ और अर्थव्यवस्था में ज्यादा गिरावट आई। इसी अध्ययन में स्टैकेनिया को देखो का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। स्टीवन में लोगों को वैयिक सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए प्रीति किया गया। इसके विपरीत डेमोक्रेट में लॉकडाउन लगाया गया। पाया गया कि स्टीवन में पांच गुना अधिक मृत्यु हुई। यिनियर्सी ऑफ ऑक्सफर्ड और 'वाइली विलनिकल प्रैविट्स' परिकार में दो अलग-अलग लेखों में इंडिलैंड के लॉकडाउन के संबंध में बताया गया कि देर से लॉकडाउन लगाने के कारण वहां मृत्यु दर अधिक हुई, जिसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा।

छैला हो लॉकडाउन- इन अध्ययनों से स्पष्ट है कि लॉकडाउन तो हमें लगाने ही पड़ेगा। लॉकडाउन नहीं लगाते हैं तो महामारी का फैलाव अधिक होता है जो अंतः अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। दूसरी तरफ अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो अर्थव्यवस्था को सीधे नुकसान होता है। इसलिए हमारे सामान सावल यह नहीं है कि लॉकडाउन किस तरह लगाया जाए, उसका कैसा हो।

लॉकडाउन विशेष स्थानों, कानूनों एवं ट्रॉकीब से लगाया जा सकता है जिससे कि अधिक दुर्घटनाक कम हो और महामारी का फैलाव भी कम हो। 'इकॉनोमिक्स टुडे' परिकार के अनुसार अगर कंट्रोल्यून यज्यों से कह कर श्रमिकों को साइट की चारियाँवारी के अंदर हो रहने की सुविधा मुहैया कराई जाए, तो अधिक गतिविधि जारी रखते हुए भी महामारी के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। इसी प्रकार की व्यवस्था कल-कारवानों में भी की जा सकती है।

यह भी देखना चाहिए कि लॉकडाउन का तात्कालिक और दीर्घकालिक कुल प्रभाव क्या है। रुकूनों में लॉकडाउन लगाने से वर्तमान में विषेष कानूनात्मक प्रभाव पड़ता है, तो भी दीर्घकाल में इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए वहां ट्रैकिंग और ट्रैसिंग की जाए। इसकी तुलना में होटल, रेस्ट्रॉन्ट, मदिर और तीर्थयात्रा पर लॉकडाउन लगा देना बेहतर है, क्योंकि इन गतिविधियों से कोविड के फैलाव की संभावना अधिक होती है।

सरकार को अलग-अलग गतिविधियों पर अलग-अलग तरकीब से लॉकडाउन लगाने के नफा-नुकसानों का आकलन करना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और उच्च शिक्षा के विद्यालयों में लॉकडाउन लगाने से सं मज्ज में किटनी बद्धता होती है, और अर्थव्यवस्था को किटनी होती है, यह देखा जाए। इसी प्रकार विदेशी यात्रा, होटल, रेस्ट्रॉन्ट, मदिर और तीर्थयात्रा को प्रतिबंधित करने से किटनी लाभ-हानि होती है, यह भी देखा जाए। कंट्रोल्यून के मामलों में भी इसे खोलो, बंद करने अथवा श्रमिकों को चारियाँवारी के अंदर रखने पर लाभ-हानि होती है। उनके अलग-अलग नफा-नुकसानों की ठीक से गणना की जानी चाहिए। तब जिस विकल्प में लाभ अधिक हो, उसको अपनाना चाहिए। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था की मूल गति बनी रह सकती है।

'वाइली विलनिकल प्रैविट्स' परिकार में इस बात पर जोर दिया गया कि लॉकडाउन को केवल ऊपर से लगाने से बात नहीं बनती है। इसमें जनता का सहयोग हासिल करना महत्वपूर्ण होता है। मेरे ध्यान में है कि पिछले वर्ष कोविड महामारी के प्राइमरी समय में न्यू यॉर्क के गवर्नर कुओतो हर रोज सुबह प्रेस बार्ट करके जनता को परिस्थिति की विस्तृत जानकारी देते थे। इसी प्रकार यदि प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रतिविनियोग जनता को जटी परिस्थिति से अवगत कराएं और स्वत्यं भी उन विधियों का पालन करें, जिनकी अपेक्षा वे जनता से करते हैं, तो जनता का उन्हें सहयोग मिलेगा। याद करें कि लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान से युद्ध के समय संपूर्ण देश का आहान किया था कि सबको सासाह में एक दिवस करना चाहिए, जिससे अगली की बद्धता हो सके। उनके आहान का संपादन गहरा प्रभाव पड़ा था क्योंकि वह स्वयं भी उस साल का निष्पार्वक पालन कर रहे थे।

-भरत झुनझुनवाला

कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था पर असर, पिछले साल की तरह जंभीर नहीं

मुंबई । कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की आधी अवधि में अर्थिक गतिविधियां प्रभावित जरूर हुई हैं लेकिन कमज़ोर नहीं पड़ी है। हालांकि संक्रियाओं की संख्या पूर्व के मुकाबले कहाँ अधिक है।



हाँ। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर आरबीआई के डिटी गवर्नर एम डी प्राप्ति विजयन ने गया है कि कोरोना वायरस महामारी का रफ्तार ने भारत और दुनिया को अचंभित किया है। इस तेजी पर अंकुश लगाने के लिये युद्ध स्तर पर अभियान चलाये गये

लोगों को घर से काम करने की व्यवस्था के लिये स्वयं को बेहतर तरीके से तैयार करना, ऑनलाइन डिलिवरी मॉडल, ई-वाणिज्य और डिजिटल भुगतान का अच्छे तरीके से काम करना इसके उदाहरण हैं।' आरबीआई ने साफ किया है कि लेख में अधिकतर विचार लेखों के हैं और कोइंग के लिये जान पड़ता है। लेख के अनुसार, 'दूसरी लहर से 2020-21 की पहली तिमाही की आधी अवधि में आरबीआई विचार लेखों के हैं और आरबीआई के लिये एक लेख से में लेख खाते हैं। लेख के अनुसार संकरण के मामलों में तेजी से वृद्धि पर रोके लगाने के लिये कई राज्यों में लगायी गयी

पार्टियों से अप्रैल और मई में वास्तविक अर्थव्यवस्था के कई संकेत हल्के पड़े। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर महानगरों, शहरों में तेज रही। यह राज्यों, क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैला है। लेख के अनुसार, 'दूसरी लहर से 2020-21 की पहली तिमाही की आधी अवधि में आरबीआई विचार लेखों के हैं और आरबीआई के लिये एक लेख से में लेख खाते हैं। लेख के अनुसार संकरण के मामलों में तेजी से वृद्धि पर रोके लगाने के लिये कई राज्यों में लगायी गयी हैं। जबकि कुल आपूर्ति पर

प्रभाव कम पड़ा है।' इसमें कहा गया है, 'हालांकि इस समय स्थिति अभी त्थिर नहीं हुई है। लेकिन जो प्रवर्ति है, उससे यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की गति पर जो असर पड़ा है, वह उतना गंभीर है। पटेल और डीजल बिक्री के प्रारंभिक अंकड़े भी भी अप्रैल में इंधन की मांग में नरमी को बताते हैं जिसका कारण आवाजाही पर आवाजाही पर असर, सोच-विचारकर किये जाने वाले खर्च और रोजगार की कमी। इसके अलावा माल भंडार पर भी असर पड़ा है लेकिन वह प्रभाव मान वालों ने आवाजाही में नरमी आयी है। माल ढुलाई और वात्रियों की आवाजाही में नरमी आयी है।

डिश टीवी के ग्राहकों ने गिरवी रखे शेयरों को खुले बाजार में बेचा

नई दिल्ली । डिटीएच सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी डिश टीवी ने आज बताया कि उसके ग्राहकों ने प्रवर्तकों द्वारा गिरवी रखे 5.11 करोड़ शेयरों को खुले बाजार में बेचा है, जिसके बाद प्रवर्तक सम्पूर्ण मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी में सीधी हिस्सेदारी 2.78 फौसदी घट



खुले बाजार में 30 दिसंबर 2020 से 12 मई 2021 के बीच चार खेप में बेचे गए।

ईरान ने भारत को दिया 3 अरब डॉलर का इटका

नई दिल्ली । भारत को ईरान में 3 अरब डॉलर की गैस परियोजना से हाथ धोना पड़ा है। ईरान ने फारसी लॉक के फैजाद-बी गैस फील्ड से भारत का दरवाजा दिखा दिया है। भारत की सरकारी तेल कंपनियों की अगुवाई वाले कंसोर्टियम के साथ एक खंडार खोजा था। ईरान ने इस कंसोर्टियम के साथ 7 जून को ईरान फरजाद-बी ने खबर दी थी कि ईरान फरजाद-बी के लिए रूस से बातीय कंसोर्टियम ने 2002 में एक्सप्लोरेशन पर साइन किए थे और 40 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। गैस भंडार की खोज के लिए ईरान ने इस परियोजना के लिए भारत के 2 अरब डॉलर के प्रस्ताव को खालिज कर दिया था। अभी यह सफ नहीं है कि भारतीय कंसोर्टियम अपने निवेश की वसूली कैसे करेगा। डील के लिए कई डेलाइन मिस हुई हैं। भारत



डील ईरान के पेट्रोलियम मिनिस्टर की उपस्थिति में हुई। यह दूसरा पॉका है जब ईरान में भारत के निवेश प्रस्ताव को झटका लगा है। पिछले साल ईरान ने चाबाहे रेलवे लिंक के लिए भारत के लिए भारत के एक साथ एक सोसायर के साथ एक बेसिक एपीएमेंट के मुताबिक ईरान की मार्च 2017 में ही सफ हो गई थी जब उसने कंसोर्टियम के साथ एपीएमेंट पर साइन किए थे और 40 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। गैस भंडार की खोज के लिए साल 2009 में ईरान ने इस परियोजना के लिए भारत के 2 अरब डॉलर के प्रस्ताव को खालिज कर दिया था। अभी यह सफ नहीं है कि भारतीय कंसोर्टियम अपने निवेश की वसूली कैसे करेगा। डील के लिए कई डेलाइन मिस हुई हैं। भारत

ने डील की शर्तों में बार-बार बदलाव और इसमें देरी के लिए ईरान